

शिक्षा तंत्र की बेबसी: कोरोना के संदर्भ में

डॉ. गायत्री शर्मा

असिस्टेंट प्रोफेसर (हिंदी),

चमेलीदेवी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल

स्टडीज़, इंदौर (म.प्र.)

98278 82950, 88394 42411,

charkli01@gmail.com

सारांश:

देश के भविष्यनिर्धारक कहे जाने वाले युवाओं को लक्ष्य बनाकर कोरोना ने देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था को भी सुनियोजित तरीके से प्रभावित किया है। युवाओं को शिक्षण संस्थानों से दूर कर कोरोना ने दुनिया को 'ऑनलाइन शिक्षण' का एक नया मंत्र दिया है, भारत में जिसके नफे कम और नुकसान अधिक है। स्मार्टफोन, इंटरनेट पैक और इंटरनेट कनेक्टिविटी के अभाव जैसी कई समस्याओं का सामना करता युवा चाहकर भी आज 'ऑनलाइन शिक्षण' की ग्राह्यता को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। वही कुछ युवा, जो ऑनलाइन शिक्षा के बहाने इंटरनेट की दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं, वे युवा भी अब कई प्रकार की शारीरिक, मानसिक व सामाजिक समस्याओं से रू-ब-रू हो रहे हैं। कोरोना के चलते इंटरनेट की आभासी दुनिया की अति नजदीकियों ने युवाओं को वास्तविक दुनिया से इतना दूर कर दिया है कि अब चाहकर भी वे 'ऑनलाइन' व 'ऑफलाइन' दुनिया में बेहतर तालमेल नहीं बना पा रहे हैं। कई शोधों के परिणाम यह भविष्यवाणी करते हैं कि कोरोना के जाने के बाद भी आने वाले वर्षों में शिक्षा-तंत्र पर इस वायरस के भविष्यगामी परिणाम और भी अधिक घातक होंगे।

की-वर्ड : कोरोना व उच्च शिक्षा, गायत्री शर्मा, भारत, कोविड 19 वायरस, ऑनलाइन शिक्षा, इंटरनेट, कम्प्यूटर, स्कूली शिक्षा, शिक्षा की आवश्यकता, दूरस्थ शिक्षा

भूमिका:

हर विकास अपने पीछे विनाश की कोई न कोई निशानी जरूर छोड़ जाता है। सामान्य लैब परीक्षण हो या दुनिया की तबाही का लक्ष्य, दोनों में से कारण कुछ भी रहा हो पर चीन के वुहान से चलकर हजारों किलोमीटर की यात्रा कर विश्वभ्रमण करने वाला कोरोना वायरस कम समय में ही हम सभी को नासूर सा दर्द दे गया है। यह सब इतना शीघ्रता से हुआ कि हम संभल पाते या कुछ समझ पाते, उससे पहले ही एक लहर के बाद दूसरी लहर और दूसरी लहर के बाद कोरोना की तीसरी लहर की आहट, जैसे मुशिकलों का सैलाब बन तेजी से हमारी ओर बढ़ रहा है।

शिक्षा किसी भी व्यक्ति की मौलिक व संवैधानिक आवश्यकता है। कहा जाता है कि यदि आपको किसी भी देश को आर्थिक व सामाजिक रूप से कमजोर करना है तो उसका सबसे बेहतर तरीका है उस देश के शिक्षा-

तंत्र को कमजोर करना। शिक्षा-तंत्र के कमजोर होते ही वह देश शनैः-शनैः अवनति की ओर अग्रसर होता चला जाएगा। चिकित्सा के बाद कोरोना ने सबसे अधिक प्रभावित देश के शिक्षा-तंत्र और युवा वर्ग को ही किया है। कोरोना लॉकडाउन ने युवाओं की पढ़ाई, रोजगार, स्वास्थ्य, सामाजिक रिश्ते, आर्थिक स्थिति आदि सभी पर अपने दूरगामी दुष्प्रभाव छोड़े हैं। अप्रैल और मई 2020 में 'ग्लोबल इनीशिएटिव कंपनी' द्वारा युवाओं पर एक सर्वे किया गया। यह सर्वे 112 देशों के लगभग 12000 छात्रों से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है। सर्वे के परिणामों के अनुसार 73 प्रतिशत छात्रों ने ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा में कोई बड़ा फर्क महसूस नहीं किया, वहीं 17 प्रतिशत छात्र ऑनलाइन शिक्षण के कारण कोरोना संक्रमण काल में चिंता और अवसाद के शिकार हुए।¹

सामान्य गणित की भाषा में एक और एक दो होते हैं पर कोरोना की गणित में एक और एक अनेक होते हैं। एक व्यक्ति के माध्यम से सैकड़ों व्यक्तियों में त्वरितता से फैलता कोरोना संक्रमण कम समय में ही बहुगुणित हो जाता है। वैक्सीनेशन महाअभियान के द्रुत स्तर पर चलाने के बावजूद भी आज देश की लगभग आधी युवा आबादी उम्र के मापदंडों पर खरी नहीं उतरने के कारण वैक्सीन से वंचित है। ऐसे युवाओं के लिए अब कोरोना के डर के बीच अपनी शिक्षा, करियर व स्वास्थ्य तीनों में तालमेल स्थापित कर पाना किसी जंग जीतने की चुनौती से कम नहीं है। आज चुनौतियां युवाओं और सरकार दोनों के लिए बराबर की है क्योंकि देश की युवा आबादी को कोरोना से महफूज रख पाना और स्कूल, कॉलेजों को पूरी तरह से अनलॉक कर पाना हमारे लिए सोचने में बड़ा आसान है पर सरकार के लिए अमल करने में बेहद मुश्किल है। कोरोना के नित-नए बदलते स्वरूप और लक्ष्य ने सरकार के इंतजामों की गणित को बुरी तरह से गड़बड़ा दिया है। कोरोना की अब तक की रफ्तार और लक्ष्य को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि संभवतः अब इसका अगला लक्ष्य बच्चे और युवा होंगे।

कोरोना के चलते स्कूलों के पूरी तरह से अनलॉक न होने से स्कूल के छात्रों को भी अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हर बच्चे की शुरूआती पाठशाला उसका घर होता है लेकिन किसी भी बच्चे की विधिवत शिक्षा की शुरूआत उसके स्कूल से होती है। स्कूली शिक्षा के बाद छात्र उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज का रुख करता है। कोरोना के डर से पिछले दो वर्षों में इन दोनों शिक्षाओं में 'गुणवत्ता' का स्थान 'औपचारिकता' ने ले लिया है। शिक्षा की महत्ता हर देश में एकसमान है। दुनियाभर के शिक्षकों के पढ़ाने के तरीके व्यक्तिशः अलग-अलग हो सकते हैं परंतु उनके पढ़ाने का लक्ष्य सदैव छात्रों को शिक्षित करने का होता है। पहली बार कोरोना महामारी के परिप्रेक्ष्य में दुनियाभर के औसतन शिक्षक एक साथ इस बात पर सहमत हैं कि कम्प्यूटर कभी भी क्लासरूम की जगह नहीं ले सकता है क्योंकि बच्चा जो ज्ञान क्लासरूम में प्राप्त करता है, वह ज्ञान उसे कम्प्यूटर पर नहीं मिल सकता है।²

स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में कोरोना से उपजी चुनौतियां:

स्कूल बच्चों को किताबों की दुनिया व अक्षरज्ञान से परिचित कराता है। जिस प्रकार कुम्हार द्वारा कच्ची माटी को आकार देकर उसे सुंदर रूप में ढाला जाता है, उसी प्रकार शिक्षकों द्वारा स्कूल में बच्चों को बेहद संजीदगी व प्यार के साथ तराशकर तैयार किया जाता है। स्कूल से ही बच्चा किताबी शिक्षा, नैतिक शिक्षा व

सामाजिक शिक्षा के रूप में बुनियादी शिक्षा प्राप्त करता है। स्कूल की दुनिया तनाव और जिम्मेदारियों से परे आनंद, उत्साह, ऊर्जा, नवीनता व उमंग की दुनिया होती है। बालपन में हम जो सीखते हैं, वो हमें जिंदगीभर याद रहता है। स्कूल के शिक्षक व मित्र भुलाए नहीं भूलते हैं। लेकिन कोरोना के कारण अधिकांश बच्चों के लिए नियमित स्कूल जाना एक सपना बन गया है। कोरोना ने शिक्षा तंत्र को जिस तरह से बर्बाद किया है, उतनी बर्बादी दुनिया में किसी और महामारी ने नहीं की है। कोरोना के चलते कई बच्चे तो अपनी विधिवत स्कूली शिक्षा का आरंभ किए बगैर ही दो साल की शिक्षा के अंतराल की पूर्ति घर बैठे ही कर गए। वहीं दूसरी ओर हाईस्कूल व हायर सेकेंडरी के अधिकांश छात्र इंटरनेट व मोबाइल के अभाव में क्लास ज्वाइन करने की औपचारिकता भी पूर्ण नहीं कर पाए और शिक्षा का यह मुश्किल पड़ाव भी हसते-हसते पार कर गए। बगैर पढ़े पास होने की चाहत में कई स्कूलों में कोरोना के दौरान धड़ल्ले से एडमिशन हुए। शिक्षा-तंत्र की इन खामियों में दोष किसी का भी हो पर भविष्य में इसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ेगा।

भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों की शिक्षा पर कोरोना के प्रभाव का आंकलन करने के लिए गए सर्वे के परिणाम बताते हैं कि ऑनलाइन शिक्षण से बच्चों की लेखन व पठन क्षमता अत्यधिक प्रभावित हुई है। ग्रामीण अंचलों के मात्र 8 प्रतिशत स्कूली छात्रों ने ही नियमित रूप से ऑनलाइन क्लास ज्वाइन में रुचि दिखाई, जबकि 37 प्रतिशत छात्र अपनी ऑनलाइन क्लासों में रुचि नहीं लेते थे। इसके पीछे कारण कई हो सकते हैं। कई बार ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि शिक्षकों के द्वारा छात्रों को समय पर ऑनलाइन स्टडी मटेरियल ही नहीं भेजे गए या फिर जो मटेरियल उनके द्वारा भेजे गए, उन्हें छात्रों के पालक स्वयं समझने में व बच्चों को समझाने में असमर्थ रहे।³

कोरोना काल में सरकार द्वारा बच्चों की शिक्षा को जारी रखने के विकल्प के तौर पर मोबाइल पर ऑनलाइन क्लास व टेलीवजन पर लेक्चरों का इंतजाम किया गया किंतु अनेक शिक्षाविद् यह मानते हैं कि बच्चों को लेक्चर के माध्यम से व्यस्त रख पाने में ये माध्यम पूरी तरह से कारगर सिद्ध नहीं हुए हैं। सही मायनों में स्कूलों में ऑनलाइन क्लास हेतु संसाधनों की कमियों का वास्तविक आंकलन तो कोरोना काल में ही हुआ है। शिक्षा विभाग के 2019-20 के आकड़ों के अनुसार कोरोना काल में भारत के 12 प्रतिशत से कम सरकारी स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा व 30 प्रतिशत से कम स्कूलों में कम्प्यूटर की सुविधा मौजूद थी। आर्थिक परेशानियों के कारण भी कोरोना ने कई बच्चों को स्कूल जाने से वंचित कर दिया या फिर प्राइवेट स्कूल से उन्हें सरकारी स्कूलों की ओर शिफ्ट कर दिया। ऑक्सफेम इंडिया के सर्वे के आंकड़े जो तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, वह और भी चौंका देने वाली हैं। हरियाणा राज्य के 12.5 लाख स्कूली छात्रों ने कोरोना के दौरान प्राइवेट स्कूलों से अपना दाखिला निकलवाकर सरकारी स्कूलों में करवाया।⁴

स्कूली शिक्षा में कोरोना के कारण जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई चंद माह में कर पाना असंभव सा है लेकिन कहते हैं कि जब जागे, जब सबेरा। अब इसी तर्ज पर ही शिक्षकों को ऑनलाइन शिक्षा की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होना होगा और छात्रों की शिक्षा पर पहले से अधिक गंभीरता से ध्यान देना होगा। यदि ऐसा होता है तो जल्द ही हम सभी मिलकर अपने बच्चों के रूप में देश के भविष्य को सुरक्षित कर पाएंगे। कोरोना

के परिप्रेक्ष्य में यह कहना अनुचित नहीं होगा कि स्कूली शिक्षा से वंचित छात्र आज समाज के लिए भी एक गंभीर चुनौती बन गए हैं क्योंकि कोरोना काल के एक लंबे समय अंतराल, आर्थिक तंगी, परिजनों की मौत आदि के दुष्परिणामस्वरूप देश में बालश्रम, बाल उत्पीड़न, बाल अपराध जैसी कई सामाजिक बुराइयों को बढ़ने के लिए अनुकूल माहौल मिला है। ऐसे में शैक्षणिक व सामाजिक दोनों चुनौतियों का सामना करने के लिए अब हमें संगठित होकर वैक्सीनेशन के जनअभियान की तरह शिक्षा का अलख जगाने के जगअभियान को आरंभ करना होगा, जिससे हम फिर से देश के नौनिहालों का रूख शिक्षा की ओर मोड़ पाएंगे।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कोरोना से उपजी चुनौतियां:

ज़िंदगी में बदलाव की दस्तक हम सभी को सुहाती है। स्कूल से निकलकर कॉलेज की ज़िंदगी बचपन से लड़कपन के दौर में प्रवेश का वो खुशनुमा पल होता है, जिसका स्वप्न हर छात्र स्कूल के दिनों से ही देखना आरंभ कर देता है। उम्र के साथ ही छात्र जीवन में करियर का भी निर्धारक मोड़ कॉलेज ही होता है। देश में कोरोना के मामले बढ़ने का खामियाजा कॉलेज में प्रवेश लेने वाले और कॉलेज छोड़ने वाले दोनों को ही भरना पड़ा। कॉलेज में अंतिम वर्ष में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए कोरोना उनकी ऑफलाइन एग्जाम के स्वप्न, ट्रेनिंग, कैंपस प्लेसमेंट आदि कई उम्मीदों पर पानी फेर गया। इसके ठीक विपरित कोरोना के साये में अपने स्कूल का इम्तेहान देने वाले वे छात्र इस वर्ष कॉलेजों में कदम ही नहीं रख पाए, जो कॉलेज में अपने दोस्तों की टोली के साथ पढ़ाई व मौज-मस्ती के इरादे से जाना चाहते थे। कड़ी पाबंदियों के चलते उनका कॉलेज में वेलकम भी ऑनलाइन हुआ और शिक्षकों से परिचय भी ऑनलाइन हुआ।

कॉलेज वह स्थान है, जहां की दुनिया, माहौल व शिक्षण प्रणाली आदि स्कूलों से बेहद अलग होती है। कॉलेज में विद्यार्थियों के नियमित छात्र के तौर पर प्रवेश लेने का प्रमुख कारण शिक्षकों के मार्गदर्शन में कॉलेज में उपस्थित होकर पढ़ाई करना होता है। नियमित अर्थात् ऑफलाइन अध्ययन के लिए कॉलेज में प्रवेश लेना और ऑनलाइन पढ़ाई करना आज छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। मात्र औपचारिकताओं की खानापूर्ति करते हुए आज भी शिक्षक व छात्र दोनों में से जो जहां है वहीं से वह ऑनलाइन क्लास लेने व क्लास अटेंड करने की मात्र औपचारिकता को पूर्ण कर रहे हैं।

वर्षभर छात्रों की चहलकदमी, सांस्कृतिक आयोजनों, खेलकूद, शोर-शराबा, छात्र राजनीति व छात्रों की उपस्थिति से गुलज़ार रहने वाले कॉलेजों ने कोरोना-काल में ऐसा सन्नाटा देखा, जिसमें कॉलेजों के भव्य व सुंदर परिसर में पक्षियों की चहचहाहट थी, ताजा स्वच्छ हवा भी थी और स्वच्छता भी थी, पर ऐसे खुशनुमा मौसम में भी वहां छात्रों की कमी खलती नज़र आ रही थी। वायरस का संक्रमण फैलने के भय के माहौल में भी कुछेक लोग कॉलेज परिसर में चहलकदमी करते नज़र आते हैं और ये वो लोग हैं, जो कोरोना के डर से मास्क व फेस शील्ड में मुंह छुपाते घुम रहे हैं। इससे भी आगे यदि इनका बस चले तो ये कोरोना के भय से खुली हवा में सांस लेने से भी गुरेज कर लें। वास्तविकता यही है कि अब कोरोना का खौफ लोगों में इस कदर घर कर गया है कि इस वायरस के संक्रमण से बचने के लिए कई पालकों ने अपने बच्चों के भविष्य का एक या दो साल बर्बाद करना स्वीकार कर

लिया किंतु कोरोना काल में अपने बच्चों का प्रवेश किसी भी कॉलेज में नहीं कराया। युवाओं में अधिकांश का दोनों डोज का वैक्सिनेशन नहीं होने से भी पालक अपने बच्चों को कॉलेज भेजने को लेकर असहमत व असमंजस की स्थिति में है। जिसे देखते हुए तो यही लगता है कि आगामी कुछ माह तक यही स्थिति देशभर में बदस्तूर कायम रहेगी।

कोरोना-काल में कॉलेज में नवीन प्रवेश व छात्रों की संख्या कम होने से उसकी भरपाई के फलस्वरूप कई शैक्षणिक संस्थानों द्वारा शिक्षकों के वेतन में कटौती व शिक्षकों की छंटनी भी की गई। ऐसे में शिक्षकों व छात्रों दोनों के भविष्य को कोरोना संक्रमण ने बुरी तरह से या यूँ कहे कि पूरी तरह से प्रभावित किया है। कोरोना की पहली व दूसरी लहर का संक्रमण के बढ़ने का दौर वो मुश्किल वक्त था, जिसमें कई कॉलेजों के लिए कोर्स के लिए आवंटित सीटों को बचा पाना, मान्यता मापदंडों पर खरा उतरना, कॉलेज संचालन हेतु पूंजी निकाल पाना और प्रवेश के समय छात्रों से किए गए वादे पूरे कर पाना बहुत मुश्किल रहा। ऐसे में कई संस्थान कोरोना काल में या तो शुरू ही नहीं किए गए या बंद कर दिए गए।

ऑनलाइन क्लास के लिए बच्चों को ऑनलाइन होना भी जरूरी है और ऑनलाइन होने के लिए स्मार्टफोन होना व उसमें नेट रिचार्ज होना भी जरूरी है। ऐसे में आर्थिक तंगी के चलते बमुश्किल कई पालक घर के एक मोबाइल में ही नेट पैक रिचार्ज करा पाते हैं। यहां त्याग बच्चों के साथ ही उनके माता-पिता को भी करना पड़ता है। ऑनलाइन क्लास के लिए माता-पिता को न चाहते हुए भी अपना मोबाइल बच्चों के हाथों में थमाना पड़ रहा है। दुविधा तो तब होती है, जब किसी घर के दो बच्चों की एक ही समय पर ऑनलाइन क्लास होती है तो ऐसे में एक के भले के लिए उन दोनों में से किसी एक को अपनी क्लास का त्याग करना पड़ता है।

कोरोना के कारण कम आमदनी वाले मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चों को अत्यधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा क्योंकि कई ग्रामीण व शहरी गरीब छात्रों के पास या तो मोबाइल नहीं था या फिर मोबाइल होने पर उसमें इंटरनेट का रिचार्ज नहीं था। ऐसे में कम संसाधनों वाले कॉलेजों ने, जिनके छात्र पहले से ही शिक्षा संबंधी कई बाधाओं से गुजर रहे थे, उन्हें अपने छात्रों व शिक्षकों को डिजिटल साक्षरता की दिशा में ऑनलाइन क्लासों के लिए तैयार करने में बड़ी परेशानियां आईं। भारत आज भी इंटरनेट साक्षरता की दिशा में पिछड़ा देश है। शिक्षा के क्षेत्र में 'नेशनल सैपल सर्वे' के आंकड़ों के मुताबिक देश में केवल 24 प्रतिशत घरों में ही इंटरनेट की सुविधा है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी द्वारा कॉलेज छात्रों पर किए गए एक सर्वे में यह सामने आया है कि केवल 37 प्रतिशत कॉलेज के छात्रों ने ही ऑनलाइन क्लासों को जारी रखने में और इसके ठीक उलट 90 प्रतिशत छात्रों ने क्लासरूम में लेक्चर लेने में अपनी सहमति जताई है। इस सर्वे में देश के शीर्षस्थ तकनीकी संस्थान आईआईटी के 10 प्रतिशत छात्रों ने कहा है कि वे इंटरनेट पर स्टडी मटीरियल डाउनलोड करने में असमर्थ हैं, जिसका कारण उन छात्रों ने अपर्याप्त इंटरनेट डेटा प्लान और नेटवर्क कनेक्टिविटी का न मिलना बताया है।⁵

ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ने वाले छात्र आज भले ही शिक्षा में अक्वल और नवीनतम तकनीक के ज्ञाता बन रहे हैं लेकिन इसके ठीक विपरित ऑनलाइन क्लासों के कारण कई शारीरिक व मानसिक समस्याओं

का सामना भी इन छात्रों को करना पड़ रहा है। सिरदर्द, तनाव, मांसपेशियों में दर्द, दृष्टिदोष, अनिद्रा आदि कई ऐसी शारीरिक समस्याएं हैं, जिनका सामना आजकल छात्र कर रहे हैं। समग्र रूप से कहे तो कोरोना के चलते ऑनलाइन शिक्षा के चलन ने बच्चों को बाहरी दुनिया से दूर करते हुए उन्हें अनेक शारीरिक समस्याओं से ग्रसित कर दिया है। ऑनलाइन क्लास के लिए नवीनतम माध्यम के रूप में प्रयोग की जाने वाली जूम या गूगल मीटिंग छात्रों को एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कराती है, जो हाइटेक तो है पर उसमें अधिकांशतः संवाद एकतरफा है, उसमें समय की कड़ी बंदिश है व एडमिन के आदेशों से बंधे रहने का बंधन भी। ऑनलाइन क्लास में एडमिन अर्थात् शिक्षकों के हाथों में आपको क्लास में एडमिट, डिसमिस, म्यूट, अनम्यूट व ब्लॉक करने जैसे कई विकल्प हैं, जो आपको इस ऑनलाइन माध्यम पर भी कड़ी बंदिशों में बांधे रखते हैं। जिसका अभिप्राय यह है कि चाहकर भी आप कक्षा में अपने शिक्षक से अनौपचारिक संवाद नहीं कर सकते हैं। तकनीकी, विज्ञान, संचार, मेडिकल आदि कई ऐसे क्षेत्र हैं, जिसमें ऑनलाइन के स्थान पर ऑफलाइन शिक्षण ही सार्थक है लेकिन मजबूरी और वक्त के इशारे ने हमें वो सब भी सीखा दिया, जो वक्त की दरकार थी।

कोरोना की तीसरी लहर फिर से देश में अपना कहर बरपाने को आमदा है, जिसके चलते पुनः लॉकडाउन लगने के डर से कई कॉलेज संचालक, छात्र व पालक असमंजस की स्थिति में हैं। कई सर्वे कंपनियों ने अपने सर्वे के माध्यम से शिक्षा-क्षेत्र में कोरोना से हुए नुकसान का संभावित आंकलन करने का प्रयास किया। 'टीमलीज एडटेक' कंपनी ने देश में 700 विद्यार्थियों और 75 विश्वविद्यालयों में अग्रणी छात्रों के बीच सर्वेक्षण किया। इस सर्वे के नतीजे चौंकाने वाले हैं क्योंकि सर्वे परिणाम बताते हैं कि सर्वे में शामिल कॉलेज के छात्रों को लगता है कि कोरोना के कारण उन्हें शिक्षा में 40 से 60 फीसदी का नुकसान हुआ है। सर्वे के परिणामों के अनुसार शिक्षा में कोरोना के कारण हुआ यह नुकसान जी-7 देशों में आंकलित शिक्षा नुकसान से दोगुना है। शिक्षा के क्षेत्र में अधिक नुकसान के प्रमुख कारण हैं - डिजिटल डिवाइस, सरकारी संस्थानों में सुस्त प्रशासन, पहले से मौजूद क्षमता में कमी, अधिकतर देशों की तुलना में लंबा लॉकडाउन और कमजोर ऑनलाइन अध्ययन या अध्यापन विषय-वस्तु का होना। इस सर्वे कंपनी के सीईओ शांतनु रूज ने कहा है कि भारत में 3.5 करोड़ विश्वविद्यालय छात्र हैं और पहले से मौजूद कई चुनौतियों के कारण कोविड-19 का यह लंबा दौर और भी संकटपूर्ण रहा है।⁶

उपसंहार या निष्कर्ष:

कोरोना कोई आसमान से उपजी आपदा नहीं है। महामारी के रूप में दुनिया में तबाही मचाने वाली यह आपदा कहीं न कहीं मानव की अतिमहात्वाकांक्षा, अतिलालसा व अति आत्मविश्वास का गंभीर परिणाम है। यहां 'अति' उपसर्ग ने परिणामों में भी दुनिया में अति नुकसान को न्यौता दे दिया है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो दुनिया से आगे निकलने की होड़ ने हमें एक झटके में समय से कई वर्षों पीछे लाकर खड़ा कर दिया है। कोरोना तो एक चेतावनी है कि हम अब भी यदि नहीं संभले तो शायद संभलने और सोचने के लिए हम बचेंगे ही नहीं।

दुनिया के नजारों को यदि फिर से बदलना है तो वक्त के रूख को भांपते हुए हमें भी बदलना होगा। अब वक्त है क्वारंटाइन सेंटर बने स्कूलों व कॉलेजों में जड़े तालों को खोलकर उन्हें फिर से आरंभ करने के लिए

शिक्षकों व छात्रों दोनों को तैयार करने का। अब वक्त है शिक्षकों को ऑनलाइन शिक्षण-पद्धति व इसके फायदों से जागरूक करने का क्योंकि जब तक शिक्षक शिक्षित नहीं होंगे तब तक छात्रों के शिक्षित होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। यह सत्य है कि कोरोना ने हमें आर्थिक, सामाजिक व मानसिक रूप से बहुत अधिक प्रभावित किया है लेकिन अब उसका जिक्र कर विलाप करने की बजाय हमें शिक्षकों व छात्रों के बीच बेहतर समझ का रिश्ता व सामंजस्य कायम करना होगा। कोरोना के कहर से डरे-सहमें छात्र जब तक मानसिक रूप से मजबूत नहीं होंगे, तब तक वे शैक्षणिक रूप से भी सशक्त नहीं बन पाएंगे। आंकड़ों का काम डराना है और एक कुशल मार्गदर्शक का कार्य बच्चों के भविष्य को संवारकर आंकड़ों को बदलना है इसलिए कोरोना पर विजय पाने के लिए शिक्षा को तकनीक, सुविधासंपन्न व सर्वग्राही बनाना होगा तभी शिक्षा के सुखद परिणाम हमारे सामने होंगे।

संदर्भ ग्रंथ:

1. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ed_emp/documents/publication/wcms_753026.pdf
2. <https://www.weforum.org/agenda/2021/03/teacher-survey-education-learning-loss/>
3. <https://scroll.in/latest/1004653/97-parents-of-underprivileged-children-in-rural-india-want-schools-to-reopen-finds-survey>
4. <https://scroll.in/article/1001846/its-500-days-since-children-went-to-school-in-india-everything-is-opening-why-arent-schools>
5. <https://www.newindianexpress.com/cities/hyderabad/2020/apr/20/covid-19-lockdown-digital-divide-among-students-forces-university-of-hyderabad-to-drop-e-classes-2132571.html>
6. <https://www.tv9hindi.com/knowledge/govt-talks-about-covid-19-impact-on-education-from-primary-to-secondary-745572.html>

कोरोना महामारी का पर्यावरण पर प्रभाव

प्रा. डॉ. शहनाज रफीक शेख

यशवंत महाविद्यालय वायगांव (नि.), वर्धा.

9970876751

shahanaj.ymy@ gmail.com

सारांश:-

आज कोरोना जैसी वैश्विक महामारी और पर्यावरणीय विसंगतियों को दूर करने के लिए विशेष मूलभूत प्रयास आवश्यक है। इस बीमारी की तरह पर्यावरणीय समस्या भी वैश्विक है। इसलिए स्थानीय सेवाओं और रोजगार को बढ़ावा देने के साथ-साथ वैश्विक संस्थाओं के सहयोग और निवेश को भी मजबूत किया जाना आवश्यक है। न केवल हरित अर्थव्यवस्था और पर्यावरणीय नवीनीकरण से जुड़े कार्यक्रम को बढ़ावा देने की जरूरत है, बल्कि व्यक्तिगत कानूनी प्रबंधकीय स्तर पर भी परिस्थितिकी प्रबंधन व संरक्षण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इन तमाम प्रयासों, नवाचारों, पारदर्शिता जवाबदेही और मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति के सहारे हम इस संकट से उबरने में कामयाब हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अपनी एक रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि भी कर चुका है कि मनुष्यों में हर 4 महीने में एक नई संक्रामक बीमारी सामने आती है। इन बीमारियों में से करीब 75 फीसद बीमारी जानवरों से आती है। इसके अतिरिक्त इंसान यह भूलता जा रहा है कि जैव विविधता को चोट पहुंचाना कितना खतरनाक हो सकता है। आज आधुनिक वैज्ञानिकता का दंभ भरने वाली तमाम आर्थिक शक्तियां इस बीमारी के आगे बेबस हैं। अगर हम मनुष्य और पर्यावरण के बीच संतुलन चाहते हैं तो अपनी जीवनशैली, नैसर्गिक उपयोगिता को इस तरह बनाना होगा जिससे प्रकृति पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े।

परिचय:-

मनुष्य और पर्यावरण के बीच संतुलन आवश्यक है। कई पर्यावरण विदों का मानना है कि, कोरोना वायरस मनुष्य और प्रकृति के बीच पैदा हुए असंतुलन का दुष्परिणाम है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अत्यधिक मांस का उत्पादन, रोगानुरोधी प्रतिरोध और बढ़ते वैश्विक तापमान जैसे कारक वन्य जन्तु विषाणुओं को मनुष्यों में फैलने और भयावह रूप धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही जलवायु संकट, विषाणु जनित रोगों से लड़ने के प्रति हमारी प्रतिरोधक क्षमता भी काम कर रही है। दरअसल विगत कुछ दशकों से हो रहे परिस्थितिकीय परिवर्तन, बेरोकटोक आर्थिक विकास और प्राकृतिक संसाधनों के बेतहाशा दोहन ने परिस्थितिकीय तंत्र के अनुचित तथा असंतुलनिय प्रयोगों को बढ़ावा दिया है। कोरोना हमारे से उत्पन्न अल्पकालिक पर्यावरणीय सुधार से अधिक संतुष्ट होने के बजाए मानव प्रकृति और आर्थिक विकास के अंतर्संबंधों को नए सिरे से परिभाषित करने की आवश्यकता है।

लॉकडाउन में पर्यावरण का परिवर्तित दृश्य:-



कोरोना महामारी से भयाक्रांत समूचे विश्व में लॉकडाउन ने पर्यावरण को स्वस्थ होने का अवकाश दे दिया है। हवा का जहर क्षीण हो गया और नदियों का जल निर्मल। भारत में जिस गंगा को साफ करने के अभियान 45 साल से चल रहे थे और बीते 5 साल में ही करीब 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने पर भी मामूली सफलता दिख रही थी। उस गंगा को 3 हफ्ते के लॉकडाउन ने निर्मल बना दिया। इतना ही नहीं चंडीगढ़ से हिमाचल की हिमालय की चोटियां दिखने लगी, जब पूरी दुनिया पर्यावरण और विकास के संतुलन पर उतनी ही गंभीरता से सोचे जितना कोरोना संकट से निपटने में सोच रही है। बड़े पैमाने पर होने वाली गतिविधियों ने हमारे शहरों की हवा को कितना जहरीला और नदियों को कितना प्रदूषित किया किंतु लाकडाउन में इसमें जो सुधार हुआ वह आश्चर्यजनक था।

कोविड-19 का पर्यावरण पर प्रभाव:-

कोविड-19 के कारण हुए वैश्विक व्यवधान ने पर्यावरण और जलवायु पर कई प्रभाव डाले हैं। आवाजाही पर प्रतिबंध और सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों की एक महत्वपूर्ण मंदी के कारण दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जल प्रदूषण में कमी के साथ कई शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है। इसके अलावा पीपीई (जैसे फेस मास्क, हैंड ग्लव्स आदि) के बढ़ते उपयोग उनके बेतरतीब निपटान और भारी मात्रा में अस्पताल के कचरे के उत्पादन से पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण पर कोविड-19 के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़े हैं।

अ) पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव:-

1) वायु प्रदूषण और जीएचजी उत्सर्जन में कमी:-

कोरोना काल में उद्योग परिवहन और कंपनियां बंद हो गईं। इसने ग्रीन हाउस गैसों (जीएचजी) के उत्सर्जन में अचानक गिरावट ला दी है। यह माना जाता है कि वाहन और विमानन उत्सर्जन के प्रमुख योगदानकर्ता हैं और परिवहन क्षेत्र के जीएचजी उत्सर्जन में क्रमशः लगभग 72 प्रतिशत और 11 प्रतिशत का योगदान करते हैं। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए वैश्विक स्तर पर कई देशों ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को प्रतिबंधित कर दिया है। कुल मिलाकर, जीवाश्म ईंधन की बहुत कम खपत जीएचजी उत्सर्जन को कम करती है, जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करती है। इसके अलावा लॉकडाउन के दौरान ऊर्जा की मांग के कारण वैश्विक कोयले की खपत भी कम हुई है।

2) जल प्रदूषण में कमी:-

लॉकडाउन अवधि के दौरान प्रदूषण के प्रमुख औद्योगिक स्रोत सिकुड़ गए या पूरी तरह से बंद हो गए थे। जिससे प्रदूषण भार को कम करने में मदद मिली। उदाहरण के लिए, भारत में लॉक डाउन तालाबंदी के दिनों में औद्योगिक प्रदूषण न होने के कारण गंगा और यमुना नदी का जल स्वच्छ निर्मल हो गया। बांग्लादेश, मलेशिया, थाईलैंड, मालदीव और इंडोनेशिया के समुद्र तट क्षेत्रों में भी जल प्रदूषण कम हुआ। यही दिनों में ट्यूनीशिया में भोजन की बर्बादी की मात्रा कम हो गई, जो अंततः मिट्टी और जल प्रदूषण को कम करती है।

3) ध्वनि प्रदूषण में कमी:-

ध्वनि प्रदूषण विभिन्न मानवीय गतिविधियों (जैसे मशीनों, वाहनों, निर्माण कार्य) से उत्पन्न ध्वनि का ऊंचा स्तर है जिससे मानव और अन्य जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यह बताया गया है कि, विश्व स्तर पर लगभग 360 मिलियन लोगों को ध्वनि प्रदूषण के कारण श्रवण हानी का खतरा है। हालांकि क्वारंटाइन और लॉकडाउन उपायों के लिए जरूरी है कि लोग घर पर रहे और दुनिया भर में महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियों और संचार को कम करें जिससे, अंततः अधिकांश शहरों में शोर का स्तर कम हो गया।

ब) पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव: -

1) जैव चिकित्सा अपशिष्ट उत्पादन में वृद्धि:-

कोविड-19 के प्रकोप के बाद से विश्व स्तर पर चिकित्सा अपशिष्ट उत्पादन में वृद्धि हुई जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा है। संदिग्ध कोविड-19 रोगियों के नमूनों संग्रह के लिए निदान बड़ी संख्या में रोगियों का उपचार और कीटाणु शोधन उद्देश्य अस्पतालों से बहुत सारे संक्रामक और जैव चिकित्सा अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिए, चीन में वुहान में प्रकोप के दौरान हर दिन 240 मीट्रिक टन से अधिक चिकित्सा कचरे का उत्पादन किया जो सामान्य समय से लगभग 190 मीटर अधिक है। फिर से भारत के अमदाबाद शहर में लॉकडाउन के पहले चरण के समय चिकित्सा अपशिष्ट उत्पादन की मात्रा 550-600 कि ग्रा /दिन से बढ़कर लगभग 1000 किग्रा/दिन कर दी गई है। कोविड-19 के कारण बांग्लादेश की राजधानी ढाका में प्रतिदिन लगभग 206 मिलियन टन चिकित्सा अपशिष्ट उत्पन्न होता है। इसके अलावा मनीला कुआलालंपुर, हनोई और बैंकॉक जैसे अन्य शहरों में भी इसी तरह की वृद्धि हुई है। जो महामारी से पहले की तुलना में प्रति दिन 154 - 280 मीटर टन अधिक चिकित्सा अपशिष्ट का उत्पादन करती है। अस्पतालों से उत्पन्न कचरे (जैसे सुई, सीरीज, पट्टी, मास्क, दस्ताने, इस्तेमाल किए गए ऊतक और छोड़ी गई दवाए आदि) को आगे संक्रमण और पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए ठीक से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, जो अब विश्व स्तर पर चिंता का विषय है।

2) सुरक्षा उपकरण में बेतरतीब निपटान:-

वर्तमान में वायरल संक्रमण से बचाव के लिए लोग फेस मास्क, हैंड ग्लव्स, और अन्य सुरक्षा उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी कचरे की मात्रा बढ़ जाती है। यह बताया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में घरेलू स्तर पर पीपीई के उपयोग में वृद्धि के कारण कचरे की मात्रा बढ़ रही है। कोविड-19 के बाद से दुनिया भर में प्लास्टिक आधारित पीपीई का उत्पादन और उपयोग बढ़ा है। हालांकि संक्रामक अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में जानकारी की कमी के कारण अधिकांश लोग इन्हें खुले स्थानों में और कुछ मामलों में घरेलू कचरे के साथ फेक देते हैं। इन कचरे के बेतरतीब डंपिंग से पानी के रास्ते में रुकावट पैदा होती है और पर्यावरण प्रदूषण बिगड़ता है। यह बताया गया है कि, फेस मास्क और अन्य प्लास्टिक आधारित सुरक्षात्मक उपकरण पर्यावरण में माइक्रोप्लास्टिक फाइबर के संभावित स्रोत हैं। आमतौर पर पॉलीप्रोफाइलीन का उपयोग एन-95 मास्क बनाने के लिए किया जाता है और टाइवैक का उपयोग सुरक्षात्मक सूट, दस्ताने और मेडिकल फेसशील्ड के लिए किया जाता है, जो लंबे समय तक बना रह सकता है और पर्यावरण के लिए विषाक्त तत्वों को छोड़ सकता है। हालांकि, विशेषज्ञ और जिम्मेदार अधिकारी घरेलू जैविक कचरे और प्लास्टिक आधारित सुरक्षात्मक उपकरण के उचित

निपटान और अलगाव के लिए सुझाव देते हैं लेकिन इन कचरे को मिलाने से रोग संक्रमण तथा अपशिष्ट श्रमिकों के वायरस के संपर्क में आने का खतरा भी बढ़ जाता है।

3) नगरपालिका ठोस अपशिष्ट उत्पादन और पुनर्चक्रण में कमी:-

नगरपालिका अपशिष्ट (जैविक और अकार्बनिक दोनों) के उत्पादन में वृद्धि का पर्यावरण पर वायु, जल और मिट्टी के प्रदूषण पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। हालांकि अपशिष्ट पुनर्चक्रण प्रदूषण को रोकने, ऊर्जा बचाने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का प्रभावी तरीका है। लेकिन महामारी के कारण कई देशों ने वायरल संक्रमण के संचरण को कम करने के लिए अपशिष्ट पुनर्चक्रण गतिविधियों को स्थगित कर दिया। उदाहरण के लिए यू.एस.ए ने कई शहरों (लगभग 46%) में रीसाइकलिंग कार्यक्रमों को प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि सरकार रीसाइकलिंग सुविधाओं में कोविड-19 के फैलने के जोखिम से चिंतित थी। यूनाइटेड किंगडम, इटली और अन्य यूरोपीय देशों ने भी संक्रमित निवासियों से अपने कचरे को छांटने से प्रतिबंधित कर दिया। कुल मिलाकर नियमित नगरपालिका अपशिष्ट प्रबंधन कचरे की वसूली और पुनर्चक्रण गतिविधियों में व्यवधान, दुनिया भर में लैंडफिलिंग और पर्यावरण प्रदूषकों में वृद्धि के कारण है।

4) कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी:-

कोविड-19 के दौरान हमने अपने प्रिय जनों के लिए ऑक्सीजन खोजने में बहुत समय बर्बाद किया। अस्पतालों की ऑक्सीजन की टंकीया खाली होने के कारण कई मरीजों की जाने चली गई। हालात यहां तक पहुंच गए कि देश भर के उद्योगों से ऑक्सीजन के परिवहन को विनियमित करने के लिए अदालतों को संज्ञान लेना पड़ा। यह एक ऐसा यंत्र है जो हवा को अंदर खींचता है और आवश्यकतानुसार ऑक्सीजन देता है। हमने लोगों को एक-एक सांस के लिए तरसते देखा है और हम इसकी कीमत का अनुभव कर चुके हैं प्रकृति से हमें जो ऑक्सीजन मिलती है वह हरित आवरण को बढ़ाने और हवा, यानी हर एक सांस को प्रदूषित न करने पर आधारित है। यह एक ऐसी चीज है, जिसके बारे में हमें ठोस कदम उठाना चाहिए हमें पर्यावरण में ऑक्सीजन के उपस्थिति की गंभीरता को महत्व देना आवश्यक है।

क) पर्यावरण संतुलन के लिए उपाय:-

- 1) हरित और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग उत्सर्जन को कम करने के लिए लोगों को निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना आवश्यक है। कम दूरी में साइकिल का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जो पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है।
- 2) सतत औद्योगिकरण के लिए कम ऊर्जा, गहन उद्योगो, स्वच्छ ईंधन और प्रौद्योगिकियों के उपयोग और मजबूत ऊर्जा कुशल नीतियों में स्थानांतरित होना आवश्यक है।
- 3) एक उद्योग के कचरे को दूसरे के कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। एक निश्चित अवधि के बाद राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बाधित किए बिना उत्सर्जन को कम करने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों को एक गोलाकार तरीके से बंद कर दिया जाना चाहिए।

- 4) जहां बड़ी संख्या में लोग काम करते हैं, किसी भी संक्रामक, संचारी रोग के प्रसार को कम करने के लिए उचित दूरी और स्वच्छ वातावरण बनाए रखना चाहिए।
- 5) दैनिक जरूरतों और वैश्विक आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए महामारी की स्थिति की तरह ऊर्जा की मांग में कटौती करना संभव नहीं है, इसलिए सौर, पवन, जलविद्युत, भूतापीय ताप और बायोमास जैसे नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग ऊर्जा की मांग को पूरा कर सकता है और जीएचजी उत्सर्जन को कम कर सकता है।
- 6) जल प्रदूषण की चुनौतियों को नियंत्रित करने के लिए औद्योगिक और नगरपालिका दोनों अपशिष्ट जल को निर्वहन से पहले ठीक से इलाज किया जाना चाहिए। इसके अलावा गैर उत्पादन प्रक्रिया जैसे शौचालय फ्लशिंग और सड़क की सफाई में उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग अतिरिक्त पानी की निकासी के बोझ को कम कर सकता है।
- 7) खतरनाक और संक्रामक चिकित्सा कचरे को दिशा निर्देशों का पालन करके ठीक से प्रबंधित किया जाना चाहिए। सरकार को उचित अपशिष्ट पृथक्करण, हैंडलिंग और निपटान के तरीकों के बारे में विभिन्न जन माध्यमों के माध्यम से व्यापक जागरूकता अभियान लागू करना चाहिए।
- 8) स्थायी आजीविका सांस्कृतिक संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए परिस्थितिक पर्यटन अभ्यास को मजबूत किया जाना चाहिए। पारिस्थितिक बहाली के लिए एक निश्चित अवधि के बाद पर्यटन स्थल को समय-समय पर बंद कर देना चाहिए।
- 9) कार्बन पदचिन्ह और वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए हमारे दैनिक जीवन में व्यवहार और इष्टतम खपत या संसाधनों को बदलना आवश्यक है, जैसे स्थानीय रूप से उगाए गए भोजन ले, खाद्य अपशिष्ट से खाद्य बनाएं। उपयोग ना होने पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बंद या अनप्लग करें और कम दूरी के लिए कार के बजाए साइकिल का उपयोग करें।
- 10) स्थाई पर्यावरणीय लक्ष्यों और वैश्विक आवरण संसाधनों की सुरक्षा जैसे की वैश्विक जलवायु और जैविक विविधता को पूरा करने के लिए संयुक्त अंतरराष्ट्रीय प्रयास आवश्यक है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यू एन पर्यावरण) जैसे जिम्मेदार अंतरराष्ट्रीय प्राधिकरण को समय उन्मुख नीतियां तैयार करने अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों की व्यवस्था करने और उचित कार्यान्वयन भूमिका निभानी चाहिए।
- 11) वृक्षों के घनत्व में वृद्धि और परिस्थितिकी तंत्र की देखभाल के फलस्वरूप हमारी धरती कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करने में सफल हो पाएगी। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि पेड़ लगाने या परिस्थितिक तंत्र को बहाल करने के लिए हमें पहले प्रकृति और समाज के साथ अपने संबंधों को बहाल करना होगा पेड़ मुख्यता भूमि

पर आधारित होते हैं। कौन इसका मालिक है, कौन इसकी रक्षा करता है और कौन इसे पुनर्जीवित करता है। उपज पर किसका अधिकार होता है यह भी एक महत्वपूर्ण पहलू है।

निष्कर्ष:-

प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से महामारी मानव जीवन और वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही है जनता पर्यावरण और जलवायु को प्रभावित कर रही है यह हमें याद दिलाता है कि कैसे हमने पर्यावरणीय घटकों की उपेक्षा की है और मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन को लागू किया है। इसके अलावा कोई नई वैश्विक प्रतिक्रिया हमें मानव जाति के लिए खतरे से निपटने के लिए मिलकर काम करना भी सिखाती है। हालांकि पर्यावरण पर कोविड-19 के प्रभाव अल्पकालिक है, संयुक्ता और प्रस्तावित समय उन्मुख प्रयास पर्यावरणीय स्थिरता को मजबूत कर सकते हैं और पृथ्वी को वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से बचा सकते हैं। बेहतर भविष्य के लिए हमें प्रकृति के साथ बिगड़ते रिश्ते सुधारने होंगे। हम प्रकृति आधारित समाधान ऊपर पर्याप्त निवेश नहीं करेंगे तो उसका असर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों की प्रगति पर पड़ेगा। यदि हम अभी पर्यावरण को नहीं बचाते तो हम सतत विकास के लक्ष्य को भी हासिल नहीं कर पाएंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. downtoearth.org.in/hindistory/wildlifebiodiversity/forest/investments-in-nature-based-solutions-need-to-triple-by-2030-77164
2. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7498239/>
3. [https://www.amarujala.com/blog/22, April, 2020](https://www.amarujala.com/blog/22-April-2020)
4. Improves the situation of environment. Jagran.com/editorial/apni-baat.pandemic-covid-19,(Jagran-special-20242327.html)